an>

Need to provide adequate compensation to farmers in Sahajahanpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहांपुर) ः इस वर्ष बेमौसम बरसात एवं ओलावृष्टि से हमारा अन्नदाता भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। माननीय सदन में किसानों की स्थिति पर अनेकों बार चिंता प्रकट की गई है। देश की केंद्र सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा के प्रभाव से किसानों के कष्ट को कम करने के लिए तथा मानवीय आधार पर भी लगभग सभी राज्यों को समुचित मुआवजा दिया गया है। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करती हूँ कि समस्त उत्तर प्रदेश के हर जिले का सर्वे किया जाये तथा हर किसान की उचित क्षतिपूर्ति की जाए। देश में कितने भी कल-कारखाने हो, कितना भी विकास हो, देश के किसान सदैव उच्च स्थान पर रहेंगे। मनुष्य की प्रथम आवश्यकता उदरपूर्ति है, अर्थात् जन्म देने वाली माता के पश्चात् किसान का ही स्थान आता है। भारत देश कितना भी विकसित हो जाए, यदि किसान दुखी है तो समस्त विकास बेमानी-सा प्रतीत होगा।

मैं आग्रह करूंगी कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि समुचित हो तथा उस राशि का वितरण न्याय संगत हो, इस प्रकार की व्यवस्था हर राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए।

मैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व करती हूँ, मेरे संसदीय क्षेत्र में 20 लाख किसान निवास करते हैं, सभी की फसलों को ओलावृष्टि से भारी नुकसान पहुंचा है। इस आपदा से अनुमानित 80 प्रतिशत गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी है। ज्यादातर किसान इस विपदा से ग्रसित हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में किसानों के नाम पर 56 करोड़ रूपया मुआवजे के रूप में दिखाया गया है जबकि वास्तविकता यह है कि 50 से 70 प्रतिशत किसान अभी भी मुआवजे से वंचित हैं। 40 से 50 प्रतिशत गांवों को अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है, जिसका मूल कारण प्रशासन द्वारा किसानों को मुआवजें स्वरूप दी गई राशि में घोर विसंगति एवं उचित वितरण न होना है। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाये, जिससे अन्नदाता को न्याय मिल सके।

अंत में, मैं आग्रह करती हूं कि किसानों को उचित मुआवजा समय पर दिया जाए, जिससे किसान इस विपदा से निकल सकें।